भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228 दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937 37] N.C.T.D. No. 228 सं DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015/CHAITRA 5, 1937 No. 37]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुघार विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 26 मार्च, 2015

दिल्ली सं.फा.12 / 06 / 2015 / डीडीसी / प्र.सु. / 2283-2452.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 27.05.2015 के मंत्रिमण्डल निर्णय सं. 2131 के अनुसार धारणाओं की सामने लाने और विश्व की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों तथा नीतियों पर विचार मंथन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यवस्थागत परिवर्तन हेतु ठोस सिफारिशें करने के उद्देश्य से, दिल्ली संवाद आयोग का गठन करती है ।

- दिल्ली संवाद आयोग का संघटन निम्न प्रकार होगा :--
 - मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (i)
- उपाध्यक्ष

श्री आशीष खेतान, सुपुत्र श्री सुरेश चन्द्र खेतान (ii)

सदस्य

अध्यक्ष

उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (iii) मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

- सदस्य
- (iv) सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (v)
- सदस्य सदस्य
- प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (vi) अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाले दो गैर सरकारी सदस्य
- (vii)
- अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जाने वाला एक सदस्य सचिव
- दिल्ली संवाद आयोग के विचारणीय विशय निम्न प्रकार होंगे: 3.
 - दिल्ली सरकार को सुभासन विशयक सलाह देना और दिल्ली को प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के क. प्रौद्योगिकी आधारित समाधान देना ।
 - दिल्ली संवाद आयोग की सिफारिशों के शीध कियान्वयन हेतु कार्यनीति तैयार करना । ख.
 - समय-समय पर दिल्ली संवाद आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान ग. हेतु सुझाव देना ।

- 4. दिल्ली संवाद आयोग अपने विजन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परामर्श के लिये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ वाले कार्यबल /समितियों का गठन कर सकता है।
- 5. दिल्ली संवाद आयोग की शर्ते निम्न प्रकार होंगी :
 - (क) आयोग का कार्यकाल वर्तमान दिल्ली सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिसका कार्यकाल 14 फरवरी को शुरू हुआ है।
 - (ख) दिल्ली संवाद आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमण्डल के निर्णय के आधार पर होगी।
 - (ग) अध्यक्ष को दिल्ली सवाद आयोग के दो गैर सरकारी_सदस्यों तथा एक सदस्य सचिव को मनोनीत करने का अधिकार होगा।
 - (घ) उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप में होंगे।
 - (ङ) दिल्ली संवाद आयोग तथा कार्यबल/समिति/समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को दिल्ली सरकार के सचिव पर लागू होने वाले मानकों के अनुसार यात्रा/मंहगाई भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
 - (च) आयोग के पूर्वानुमोदन से आयोग तथा कार्यबल सामान्य या विशेष कार्यों के लिए व्यवसायिक विशेषज्ञों को प्रतियोगी बाज़ार दर पर रख सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, अरूण बरोका, सचिव (प्रशासनिक सुधार)

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 26th March, 2015

No.12/06/2015/DDC/AR/2283-2452.—The Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to set up the Delhi Dialogue Commission vide Cabinet Decision No. 2131 dated the 27th February, 2015, to consider ideas, identify the best practices and policies from around the world and translate these into concrete recommendations to the Government of NCT of Delhi for transformative change.

- 2. The composition of Delhi Dialogue Commission shall be as under:-
 - (i) The Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi Chairperson.
 - (ii) Sh. Ashish Khetan, S/o Sh. Suresh Chandra Khetan Vice Chairperson.
 - (iii) The Deputy Chief Minister, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (iv) Chief Secretary, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (v) Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi-Member.
 - (vi) Pr. Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi-Member.
 - (vii) Two non-official members to be appointed by the Chairperson.
 - (viii) A Member Secretary to be appointed by the Chairperson.
- 3. Terms of Reference of Delhi Dialogue Commission shall be as under:
 - (a) to advise Government of NCT of Delhi on governance and technological solutions to various problems afflicting Delhi
 - (b) to evolve strategy(s) for expeditious implementation of the recommendations made by the Delhi Dialogue Commission
 - (c) to suggest from time to time, remedies to overcome the bottlenecks experienced in implementation of the recommendations of Delhi Dialogue Commission
- 4. Delhi Dialogue Commission may constitute Task forces/ Committees, on various subjects consisting of experts, to advise the Commission for fulfilment of the vision of the Delhi Dialogue Commission.
- 5. The Terms and Conditions of the Delhi Dialogue Commission shall be as under:

- (a) The term of the Commission will be co-terminus with the term of the present Government of the NCT of Delhi, which assumed office on 14th February, 2015.
- (b) Vice chairperson of Delhi Dialogue Commission shall be appointed by a decision of the Cabinet.
- (c) The Chairperson shall have the powers to nominate two non-official members and a member secretary to Delhi Dialogue Commission and they shall hold office at the pleasure of the Chairperson.
- (d) The Vice Chairperson and non-official members shall be honorary positions.
- (e) The non-official members of the Delhi Dialogue Commission and the Task Force(s)/ Committee(s) will be paid TA/DA as per government norms applicable to the Secretary to the Government of NCT of Delhi.
- (f) The Commission and the Task Force with the previous approval of the Commission can hire professional experts from the market at competitive market rates, for general or specific Tasks.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, ARUN BAROKA, Secy. (AR)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सं. फा. 14(2)/एलए—2015/cons2law/15.24.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप—राज्यपाल की सहमति दिनांक 26 मार्च, 2014 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

"दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम 02)

(25मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[26 मार्च, 2015]

वर्ष 2015—2016 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2015 है।

9437,50,00,000/- रुपयों का वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए नौ हजार चार सौं सैतीस करोड पचास लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015—2016 की अविध के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविध के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (घारा 2 और घारा 3 देखिए)

(रुपये हजारो में)

अनुदान	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
संख्यांक				4	5
1	2		3	The state of the s	
	विधान मंडल	राजस्व	43000	1900	44900
1	साधारण प्रशासन	राजस्व	375375	30425	405800
2	न्याय प्रशासन	राजस्व	1565362	480238	2045600
3	जाव असारा ।	पूंजी	2500	00	2500
	वित्त	राजस्व	610003	12	610015
4	MC	पूंजी	32125	00	32125
-	गृह	राजस्व	1140050	1250	1141300
5	·fe	पूंजी	60075	00	60075
_	शिक्षा	राजस्व	15123012	763	15123775
6	Klan	पूंजी	429600	00	429600
	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	9642580	2362	9644942
7	Idiaka ana ana	पूंजी	373458	00	373458
_	सामाजिक कल्याण	राजस्व	8823425	00	8823425
8	Chillional art at 1	पूंजी	3548000	00	3548000
_	उद्योग	राजस्व	606785	125	606910
9	ઉધાય	पूंजी	90675	00	90675
40	विकास	राजस्व	4713915	835	4714750
10	Idanti	पूंजी	759950	75	760025
	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	21307775	150	21307925
11	KIGN 1447N AND WILLIAM	पूंजी	11809500	00	11809500
	लोक ऋण	राजस्व	00	8068000	8068000
	CHAN NO 1	पूंजी	00	4412950	4412950
40	ऋण	पूंजी	6250	00	6250
12	_{अंट} न पेंशन	राजस्व	312500	00	312500
13	7417				
	योग	Participated For States of States and Co. Co. Co.	81375915	12999085	94375000
	~ 11 −1		- Andrew		

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS **NOTIFICATIONS**

Delhi, the 26th March, 2015

No. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/15-24. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th March, 2014 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (Vote on Account) ACT, 2015 (DELHI ACT 02 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 25th March, 2015)

[26th March, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

issue of

Rs.9437,50,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

Appropriation.

- This Act may be called the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 1.
- From and out of the Consolidated Fund of the National Capital 2. Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees Nine thousand four hundred thirty seven crore fifty lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
- The sums authorised to be paid and applied from and Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this for the services and purposes expressed in Act, shall be appropriated the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE (See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes	4 ,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
I	Legislature	Revenue	43000	1900	44900
2	General Administration	Revenue	375375	30425	405800
3	Administrative of Justice	Revenue	1565362	480238	2045600
-		Capital	2500	00	2500
4	Finance	Revenue	610003	12	610013
·	<u></u>	Capital	32125	00	32125
5	Home	Revenue	1140050	1250	1141300
_		Capital	60075	00	6007
6	Education	Revenue	15123012	763	1512377
	·	Capital	429600	00	42960
7	Medical and Public Health	Revenue	9642580	2362	964494
,		Capital	373458	00	37345
8	Social Welfare	Revenue	8823425	00	882342
		Capital	3548000	0	354800
9	Industries	Revenue	606785	125	60691
		Capital	90675	00	9067
10	Development	Revenue	4713915	835	471475

6	DELHI GA	DELHI GAZETTE: EXTRAORDINART			
		Capital	759950	75	760025
- 11	Urban Development and Public Works	Revenue	21307775	150	21307925
		Capital	11809500	00	11809500
PD	Public Debt.	Revenue	00	8068000	8068000
		Capital	00	4412950	4412950
12	Loans	Capital	6250	00	6250
13	Pension	Revenue	312500	00	312500
	Total		81375915	12999085	94375000

सं0 फा0 14(2)/एलए-2015/ cons2law/5-14.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 26 मार्च. 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2015 (2015 का दिल्ली अधिनियम 01)

(24 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[26 मार्च, 2015]

वर्ष 2013-14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्श में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिख्ति रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त शीर्षक्र।

 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015 है।

351,98,16,000 / — रुपयों का वर्ष 2014—2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ इक्यावन करोड अठानवे लाख सोलह हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2014–2015 की अविधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और घारा 3 देखिए)

(रुपये हजारो मे)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	153850	550	154400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	858660	00	858660
4	वित्त	राजस्व	400	00	400
5	गृह	राजस्व	81700	00	81700
6	शिक्षा	राजस्व	2600	50	2650
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	1750	00	1750
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व पूंजी	2349000 500	00 00	2349000 500
		Y-11	300	00	300
9	उद्योग	राजस्व	400	8156	8556
10	विकास	राजस्व	800	00	800
		पूंजी	100	1300	1400
11	भाहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2400	00	2400
	·	पूंजी	57300	00	57300
	लोक ऋण	राजस्व	00	100	100
		पूंजी	00	200	200
	योग		3509460	10356	3519816

सौरभ कुलश्रेश्ठ अतिरिक्त सचिव

NO. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/5-14-. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th March, 2015 and is hereby published for general information:

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2015 (DELHI ACT 01 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th March, 2015)
[26th March, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2014-15

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

issue of

Rs.351,98,16,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2014-2015.

Appropriation.

- 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2015.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred fifty one crore ninety eight lac sixteen thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2014-2015 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.
- 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	153850	550	154400
3	Administrative of Justice	Revenue	858660	00	858660
4	Finance	Revenue	400	00	400
5	Home	Revenue	81700	00	81700
6	Education	Revenue	2600	50	2650
7	Medical and Public Health	Revenue	1750	00	1750
8	Social Welfare	Revenue	2349000	00	2349000
		Capital	500	00	500
9	Industries	Revenue	400	8156	8556
10	Development	Revenue	800	00	800
		Capital	100	1300	1400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2400	00	2400
		Capital	57300	00	57300
PD	Public Debt.	Revenue	00	100	100
		Capital	00	200	200
-ti-	Total	77.2.4	3509460	10356	3519816

Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.